सरकारी कर्मचारियों और कमजोर वर्गों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

1647. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हर मोहन सिंह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों तथा कमजोर वर्गों के लिए कुल कितने क्वार्टर निर्मित किये गये ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने क्वार्टरों का निर्माण किये जाने की संभावना है ;

(ग) इनमें से अब तक कितने क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं ; और

(घ) क्या उपर्युक्त कार्य में कोई विलम्ब हुआ है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान सामान्य पूल के 2575 क्वार्टर बनाए गए हैं और 1000 क्वाटरों को चालू वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान पूरा किए जाने की सम्भावना है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपने बजट प्रावधानों से चलायी जाती है। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस योजना के तहत वर्ष 1993-94 के दौरान 1,22,895 रिहायशी मकान बनाए गए। वर्ष 1994-95 के दौरान 91,990 मकानों का लक्ष्य है जिनमें से 37,999 मकान सितम्बर, 1994 तक पूरे हो गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विधवाओं के लिए आवास यूनिट

1648. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीकृत योजना के अन्तर्गत विधवाओं को रहने के लिए आवास यूनिट उपलब्ध कराने की कोई योजना शुरू की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की गई थी और उस योजना में कितनी विधवा महिलाओं को तत्काल आवास यूनिट देने का लक्ष्य था ;

(ग) क्या इन आवास यूनिटों को उपलब्ध कराने के लिए विधवाओं से कोई धनराशी वसूल की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो कब और इस संबंध में कितनी धनराशी ली गयी थी और क्या ऐसी सभी महिलाओं को अब तक आवास यूनिट उपलब्ध करा दिये गये हैं ;

(ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उन्हें आवास यूनिट उपलब्ध कराने के क्या कारण हैं ; और

(च) इस संबंध में दिनांक 15 नवम्बर, 1994 को "दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) दिनांक 5-11-94 के दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार बाबत वस्तु स्थिति इस प्रकार है :—

700 रुपये तक की मासिक आय वाले महिला-मुखिया परिवारों के लिए एक सहकारी समूह आवास परियोजना बेघरों के लिये घर अन्तर-राष्ट्रीय वर्ग, 1987 के दौरान प्रयोग योजना के रूप में शाहदरा नई दिल्ली में शुरू की गई थी।

एक सहकारी समिति अर्थात स्वयम् सेवा सहकारी आवास समिति, जिसमें 341 सदस्य हैं। सेवा दिल्ली नामक एक स्वंयसेवी संगठन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लमविंग) और हुडको के सहयोग से शुरू की गई थी। इसे जहां स्लम विंग ने रियायती दरों पर भूमि आवंटित की वहीं हुडको द्वारा परियोजना के लिए ऋण सहायता दी गई।